

भारत सरकार  
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय  
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 3587  
10 अगस्त, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: राष्ट्रीय तिलहन और पाम ऑयल मिशन

3587. डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय तिलहन और पाम ऑयल मिशन कार्यान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार मिशन की शुरुआत से अब तक तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रही है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्तमान में देश में तिलहन की अनुमानित आवश्यकता कितनी है और तिलहन का कुल बुआई क्षेत्र कितना है;

(घ) क्या सरकार ने तिलहन के बुआई क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) सरकार को तिलहन के आयात को कम करने के लिए तिलहन के उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के लिए किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है?

**उत्तर**

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)**

(क) और (ख): जी, हां। राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पाम मिशन (एनएमओओपी) की शुरुआत वर्ष 2014-15 में की गई थी और इसे वर्ष 2018-19 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के साथ एनएफएसएम (ओएसएंडओपी) के रूप में मिला दिया गया था तथा यह वर्ष 2021-22 के दौरान सामान्य राज्यों के लिए 60:40, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों के लिए 90:10 तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100 प्रतिशत की वित्तीय पद्धति के साथ केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में जारी रहा।

तिलहन का उत्पादन जो वर्ष 2014-15 में 275 लाख टन था तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार 2020-21 में बढ़कर 365.7 लाख टन हो गया था। इसी प्रकार तिलहन की खेती के तहत क्षेत्रफल वर्ष 2014-15 के 256 लाख हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2020-21 में तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार 288 लाख हेक्टेयर हो गया था।

(ग): वर्ष 2021-22 के लिए तिलहन हेतु उत्पादन का लक्ष्य 384 लाख टन निर्धारित किया गया है। वर्ष 2020-21 के दौरान तिलहन के तहत 288 लाख हेक्टेयर (तीसरा अग्रिम अनुमान) क्षेत्र बोया गया था और वर्तमान वर्ष (2021-22) के दौरान खरीफ 2021 (दिनांक 06.08.2021 तक) के दौरान तिलहन के तहत 173.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है।

(घ) एवं (ड.): एनएफएसएम (तिलहन) के लिए प्रजनक बीजों की खरीद, आधारी और प्रमाणित बीजों का उत्पादन, प्रमाणित बीजों, पौध संरक्षण उपकरणों एवं रसायनों का वितरण, जिप्सम/पायराइट/चूना/ सिंगल सुपर फास्फेट, न्यूक्लियर हाइड्रोसिस विषाणु का वितरण, उन्नत कृषि उपस्करों, स्पिंकलर सेटों, स्रोत से खेत तक पानी ले जाने वाले पाईपों की आपूर्ति, एकीकृत कीट प्रबंधन, किसानों, अधिकारियों और विस्तार कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण जैसी पहलें चलाई जाती हैं। किसानों को तिलहन मिनीकिट कार्यक्रमों के माध्यम से तिलहन की नई निर्मुक्त की गई उच्च उपज वाली किस्में भी वितरित की जाती हैं। इसके अलावा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)/कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके) के माध्यम से किसानों के खेतों में फ्रंट लाइन प्रदर्शनों (एफएलडी) और कलस्टर फ्रंट लाइन प्रदर्शनों (सीएफएलडी) के जरिए प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण भी किया जाता है।

रबी 2020-21 के दौरान तोरिया व सरसों पर एक विशेष कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन वर्ष 2019-20 के 91.23 लाख टन से बढ़कर 2020-21 (तीसरा अग्रिम अनुमान) में 99.80 लाख टन तक पहुंच गया है। खरीफ 2021 के लिए सभी प्रमुख तिलहन उत्पादक राज्यों में वितरण हेतु सोयाबीन, मूंगफली और तिल की उच्च उपज वाली किस्मों की कुल 922935 तिलहन मिनीकिट आवंटित की गई हैं। विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	तिलहन फसल	राज्य और जिला	मिनीकिट की सं.
1.	मूंगफली	7 राज्य और 53 जिले	74000
2	सोयाबीन	9 राज्य और 90 जिले	816435
3	तिल	9 राज्य और 50 जिले	32500
	कुल	-	922935

उपर्युक्त पहलों के कारण तिलहन का उत्पादन 314.59 लाख टन (2017-18) से बढ़कर 365.65 लाख टन (2020-21) हो गया है जबकि खाद्य तेलों का आयात 2017-18 के 154.00 लाख टन से घटकर 2020-21 में 133.70 लाख टन हो गया है।

\*\*\*\*\*